Pinky Rani
Assistant Professor (Guest Faculty)
Department of Economics
Maharaja College
Veer Kunwar Singh University, Ara
B.A. Economics
B.A. Part-2
Paper-4
Topic: **12वां वित्त आयोग:**

12वां वित्त आयोग:

भारत के बारहवें वित्त आयोग की नियुक्ति 1 नवंबर 2002 को संघ और राज्यों के बीच साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय के वितरण पर सिफारिशें करने के लिए की गई थी। आयोग के अध्यक्ष सी. रंगराजन थे। आयोग ने 30 नवंबर 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2005-10 की अवधि को कवर किया।

सदस्य:

आयोग के सदस्य थे:

- **डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष**
- **श्री टी.आर. प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त)**
- **प्रो. डी.के. श्रीवास्तव**
- **श्री सोम पाल, अंशकालिक सदस्य, ने 14 मई 2004 को इस्तीफा दे दिया**
- **डॉ. शंकर एन. आचार्य, अंशकालिक सदस्य,**

सिफारिशें:

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक वित्त का पुनर्गठन:

(i) केंद्र और राज्यों को 2009-10 तक संयुक्त कर-जीडीपी अनुपात को 17.6 प्रतिशत तक सुधारना है।

(ii) ऐतिहासिक विनिमय दरों पर मापे गए बाह्य ऋण के साथ संयुक्त ऋण-जीडीपी अनुपात को 2009-10 तक 75 प्रतिशत तक कम किया जाना।

(iii) केंद्र और राज्यों के लिए जीडीपी लक्ष्य के लिए राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत निर्धारित किया जाना।

(iv) केंद्र और राज्यों के राजस्व घाटे को 2008-09 तक शून्य पर लाया जाना।

(v) राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान को केंद्र और राज्यों के मामले में क्रमश: 28 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक कम किया जाना।

(vi) राज्यों को भर्ती नीति का इस तरह से पालन करना चाहिए कि राजस्व व्यय के सापेक्ष कुल वेतन बिल, ब्याज भुगतान के बाद, 35 प्रतिशत से अधिक न हो।

(vii) प्रत्येक राज्य को 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक कम करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाना चाहिए।

(viii) आगे उधार देने की प्रणाली को समय के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक लक्ष्य केंद्र और राज्यों दोनों के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात को 28 प्रतिशत तक लाना होना चाहिए।